Re: Expediting the process for funding permanent political solution to the long pending demands of the people from Darjeeling, West Bengal

श्री राजू बिष्ट **(**दार्जिलिंग**):** सभापति महोदय, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स चार इंटरनेशनल बार्डर से लगा हुआ क्षेत्र है । इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटजिक और संवेदनशील है । पूरा दार्जिलिंग हिल्स, तराई, डुआर्स क्षेत्र एक विशेष एडिमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री रखता रहा है । नॉन-रेगुलेटेड एरिया, रेगुलेटेड एरिया, शेड्यूल डिस्ट्रिक्स, बैकवार्ड ट्रैक, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया जैसी व्यवस्था रही है ।

लेकिन आजादी के बाद कुशल संवैधानिक शासन नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता की उपेक्षा होती रही । केन्द्र सरकार द्वारा लगातार हमारे क्षेत्र के विकास के लिए धन आबंटित किया गया, लेकिन धरातल पर राशि जनता तक नहीं पहुंच पा रही है । हमारे इंस्टीट्यूशन्स बंद हो रहे हैं । रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, युवा बेरोजगार हैं । क्षेत्र बुनियादी सुविधा से वंचित है । पूरा क्षेत्र डेमोग्रेफिक चेंज से समस्याग्रस्त है । संवैधानिक अधिकार से जनता वंचित है । गोरखा, राजबंशी, आदिवासी, कूच, मेक, टोटो, बंगाली, हिन्दीवासी और अन्य मूल निवासी खतरे में हैं । हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है । राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि से भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र को सुरक्षित रखना राष्ट्र हित में अति आवश्यक है । हमें संवैधानिक न्याय एवं स्थायी समाधान चाहिए, जो हमारे क्षेत्र के लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का शासन सुनिश्चित करें ।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि कृपया स्थायी समाधान में तेजी लाएं ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को जल्द न्याय मिल सकें ।